दैनिक **लोक टुडे** — जनता की आवाज...

विश्वसनीय खबरों का सर्वश्रेष्ठ अखबार

PK टाइम्स

pktimesnews.com | loktodaynews.com | PK Times News | thepktimesofficial | pk_timesofficial

वर्ष: 13 अंक: 33 | मूल्य: 1.00 रुपए | पृष्ठ: 4 | बुधवार 19 अगस्त 2026 | RNI No. RAJHIN/2013/50649

71 पीएम ई-बसों का शुभारंभ, जयपुर-भीलवाड़ा की 24 ई-बस,अलवर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर की 47 ई-बस शामिल

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लगभग 3,500 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का किया लोकार्पण-शिलान्यास

1.32 लाख से ज्यादा श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को 154 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि डीबीटी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास' के मूलमंत्र के साथ काम कर रही डबल इंजन सरकार- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

लोक टुडे

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास' के मूलमंत्र के साथ ही डबल इंजन सरकार ग्रीन और क्लीन एनर्जी की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ा रही है। इसी क्रम में जयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों में लगभग 3 हजार 500 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास करने के साथ 71 पीएम ई-बसों को रवाना किया गया है। ये विकास कार्य एवं परियोजनाएं विकसित राजस्थान-2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगी।

मुख्यमंत्री मंगलवार को एचसीएम रीपा में प्रदेशवासियों को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देने के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और प्रदूषण मुक्त भविष्य की मजबूत नींव बन चुकी है। चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार, ऑटो इंडस्ट्री के लिए पीएलआई स्कीम और पीएम ई-ड्राइव जैसी पहल से ईवी इकोसिस्टम सुदृढ़ हो रहा हैं। यही कारण है कि वर्ष 2016 के बाद से देश में ईवी की बिक्री लगभग 46 गुना बढ़ी है।

मुख्यमंत्री की प्रदेशवासियों को सौगातें

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विभिन्न शहरों के लिए लगभग 3 हजार 500 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने कुल 71 पीएम ई-बसों का शुभारंभ भी किया, जिनमें जयपुर एवं भीलवाड़ा की 24 ई-बसों का जयपुर से तथा अलवर, अजमेर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर की 47 ई-बसों का वर्चुअल शुभारंभ शामिल है। कार्यक्रम में श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत एक लाख 32 हजार 421 श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को 154 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। श्रमिकों को डिजिटल गैस डिटेक्टर एवं फायर रेस्क्यू किट वितरित किए गए। स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा है। राज्य सरकार जल, विद्युत, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार जैसे मूलभूत मुद्दों पर गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि राजस्थान आने वाले समय में समस्याविहीन और विकसित प्रदेश के रूप में देश में अपनी अलग पहचान बनाएगा। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सांसद मंजू शर्मा तथा विधायक कालीचरण सराफ, गोपाल शर्मा और कैलाश वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

इन कार्यों का हुआ लोकार्पण:-

- आरयूएचएस जयपुर में 128 स्लाइस सीटी स्कैन मशीनें एवं 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीन
- आरयूएचएस जयपुर में 18 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से स्नातक छात्रावास
- एसएमएस अस्पताल के आयुष्मान टावर के अंतर्गत कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज संस्थान
- चांदपोल के जनाना अस्पताल में 51 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से नवीन आईपीडी टावर
- झोटवाड़ा के अभयपुर और दूदू विधानसभा के रेहलाना में उप स्वास्थ्य केन्द्र जनता को समर्पित
- राजस्थान पुलिस अकादमी में 12 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित 300 प्रशिक्षुओं की क्षमता वाला महिला छात्रावास
- अजमेर में लगभग 24 करोड़ रुपये की राशि से सड़क निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण
- प्रदेश के नगरीय निकायों में 109 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित 395 पिंक टॉयलेट सहित 506 शौचालय
- 57 निकायों में लगभग 19 करोड़ रुपये की लागत से एलईडी स्ट्रीट लाइट सहित विभिन्न विकास कार्य

इन कार्यों का हुआ शिलान्यास:-

- नगरीय निकायों में बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 625 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के 76 विकास कार्य
- अमृत 2.0 योजना के तहत जयपुर नगर निगम क्षेत्र में 465 करोड़ रुपये से अधिक के सीवरेज संबंधी कार्य, 507 किलोमीटर से अधिक की बिछेगी सीवर लाइन, 52 हजार आवासों को सीवर कनेक्शन से लगभग 13 लाख नागरिकों को मिलेगा लाभ
- जयपुर में ट्रैफिक सुधार के लिए 81 करोड़ रुपये की लागत के सात कार्य, करतापुरा नाले के पास अण्डरब्रिज, अजमेर रोड पर पुरानी चुंगी जंक्शन पर अण्डरब्रिज, सीकर रोड, महल रोड और न्यू सांगानेर रोड पर यू-टर्न एवं सब-वे निर्माण सहित अन्य कार्य
- टोंक रोड और महल रोड को जोड़ने के लिए लगभग 60 करोड़ रुपये से यातायात विकास कार्य
- द्रव्यवती नदी पर 35 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से रूफटॉप सोलर
- झोटवाड़ा जयपुर में सैटेलाइट चिकित्सालय सहित विभिन्न विकास कार्य

मुख्यमंत्री का युवा सीएलजी सदस्य एवं सुरक्षा सखियों से संवाद, युवा सीएलजी सदस्य एवं सुरक्षा सखियां सामाजिक समन्वय एवं समरसता के अग्रदूत

सरकार के प्रयास एवं जन भागीदारी से सुरक्षित और अपराध मुक्त हो रहा राजस्थान

नशे और साइबर क्राइम के खिलाफ महिला और युवा शक्ति मिलकर करें प्रहार, युवा देश के कर्णधार, माता-पिता का सपना करें साकार

राष्ट्र निर्माण में करें सकारात्मक ऊर्जा का संचार- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

लोक टुडे

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार के प्रयास एवं जन भागीदारी से राजस्थान सुरक्षित और अपराधमुक्त हो रहा है। युवा सीएलजी सदस्य और सुरक्षा सखियां सहयोग एवं समन्वय से समाज में समरसता लाने एवं कानून व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में अग्रदूत साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में युवा सीएलजी सदस्यों एवं सुरक्षा सखियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के निर्माण में पुलिस के साथ समाज की सक्रिय सहभागिता भी आवश्यक है। नशे और साइबर अपराध के खिलाफ महिला एवं युवा शक्ति को मिलकर प्रभावी प्रहार करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास के मूलमंत्र को आत्मसात कर राज्य सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। सरकार किसान, युवा, महिला और गरीब को केंद्र में रखकर विकसित राजस्थान-2047 के लक्ष्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि युवा देश के कर्णधार हैं, उनकी सकारात्मक ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाना जरूरी है। युवा महापुरुषों की जीवनी पढ़ें और उनके तप, त्याग एवं आदर्शों को जीवन में अपनाएं। सुरक्षा सखी और युवा सीएलजी सदस्य अपराधों की रोकथाम के साथ यातायात व्यवस्था, रक्तदान, पौधारोपण, खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन और बुजुर्गों की समस्याओं के समाधान में भी सहयोग करें। बेहतर कार्य करने वाले सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा।

महिलाओं में विश्वास का दूसरा नाम बनीं सुरक्षा सखियां –

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा सखी योजना महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए राजस्थान पुलिस की महत्वपूर्ण पहल है। प्रत्येक थाने पर 20 से 30 सुरक्षा सखियों का चयन किया गया है और अब तक प्रदेश में करीब 22 हजार सुरक्षा सखियों का चयन हो चुका है, इनमें आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, अध्यापिका, प्राचार्य तथा महिला कार्मिक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा सखियों की भूमिका केवल सूचना देने तक सीमित नहीं है, उनका दायित्व महिलाओं में विश्वास और सुरक्षा की भावना पैदा करना भी है।

नशामुक्ति और साइबर सुरक्षा जागरूकता में युवा निभाएं भूमिका–

उन्होंने युवा सीएलजी सदस्यों से अपने क्षेत्रों में युवाओं को नशे से दूर रखने, महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नशा केवल एक युवा का भविष्य खराब नहीं करता, बल्कि उसके परिवार और पूरे समाज को प्रभावित करता है। हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान का युवा नशे और अपराध से दूर रहकर स्वस्थ, जागरूक और नेतृत्व की भूमिका निभाने वाला बने।

सीएलजी सदस्य पुलिस और जनता के बीच सेतु–

उन्होंने कहा कि सीएलजी सदस्य जनता और पुलिस के बीच विश्वास का मजबूत सेतु हैं। एक छोटी-सी सूचना भी किसी बड़ी घटना को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। उन्होंने सीएलजी सदस्यों से छोटे विवादों, पड़ोस के झगड़ों और आपसी कहासुनी जैसे मामलों में अपने स्तर पर विवेकपूर्ण और निष्पक्ष समझाइश एवं सुलह का प्रयास करने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस और आमजन के प्रति संवेदनशीलता की नीति पर काम कर रही है। सरकार की मंशा है कि कानून तोड़ने वालों के साथ सख्ती हो और पीड़ितों को पुलिस से सम्मान और संवेदनशील व्यवहार मिले।

युवाओं के लिए रोजगार और पारदर्शी भर्ती पर फोकस–

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पेपरलीक के दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए एसआईटी का गठन किया। पेपरलीक के मामलों में एसआईटी 569 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल में अब तक 410 परीक्षाएं बिना किसी पेपर लीक के आयोजित की गई हैं। करीब 1 लाख 89 हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं, जबकि 1 लाख 22 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है और 70 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। निजी क्षेत्र में भी साढ़े चार लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।

महिला सशक्तीकरण के लिए निरंतर प्रयास कर रही सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 14 लाख साइकिलों का वितरण किया गया है तथा 46 हजार मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान की गई हैं। मा वाउचर योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को निशुल्क सोनोग्राफी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 4 लाख 82 हजार से अधिक कूपन जारी किए गए हैं। वहीं 19 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में

लाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करने वाले प्रदेश के रूप में पहचान मजबूत की है। अच्छी कानून-व्यवस्था के लिए पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन अपराध की रोकथाम और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आमजन का सहयोग जरूरी है। कार्यक्रम में विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा सहित बड़ी संख्या में सुरक्षा सखियां एवं युवा सीएलजी सदस्य उपस्थित रहे। वहीं, अन्य जिलों की महिला सुरक्षा सखियां एवं युवा सीएलजी सदस्य वीसी के माध्यम से आयोजन से जुड़े।

सम्पादकीय

“मानवता सुख शांति प्रेम का, अखिल विश्व में हो
विस्तारस्वतंत्रता का हनन न होवे, रहे सुरक्षित जन अधिकार”

भारत के लिए सतर्क रहने का समय

सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्किये के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सात अगस्त को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मक्का समझौता नाम से हुआ यह करार पश्चिम एशिया के सामरिक परिदृश्य की दृष्टि से एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। समझौते के अनुसार इसमें शामिल किसी भी देश पर सशस्त्र हमला सभी तीनों पर हमला माना जाएगा। इसमें खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान, संयुक्त युद्धाभ्यास, सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा-औद्योगिक साझेदारी को मजबूती देने की बात भी कही गई है। भारत के दृष्टिकोण से इस समझौते को देखें तो सीधे तौर पर यह उसके विरुद्ध कोई लामबंदी नहीं, लेकिन इस चिंता को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि यह पश्चिम एशिया के तेजी से बदलते सुरक्षा ढांचे में पाकिस्तान की स्थिति को मजबूत कर सकता है। इसमें भारत के समक्ष वास्तविक चुनौती यह सुनिश्चित करने की होगी कि सऊदी-तुर्किये-पाकिस्तान के बीच आकार लेता यह सुरक्षा गठजोड़ फारस की खाड़ी के देशों के साथ भारत के बढ़ते सामरिक और आर्थिक संबंधों के आड़े न आए।

> सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान के बीच हुए मक्का समझौते से पश्चिम एशिया में पाकिस्तान की स्थिति मजबूत हो सकती है, जिससे भारत को सतर्क रहने की आवश्यकता है

इस समझौते को बढ़ते क्षेत्रीय असंतुलन और पश्चिम एशिया में अमेरिकी सुरक्षा भूमिका के भविष्य को लेकर बनी अनिश्चितता के परिप्रेक्ष्य में बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल की कार्रवाई के दुष्प्रभावों, खाड़ी क्षेत्र के बुनियादी ढांचे एवं समुद्री मार्गों पर ईरान और उसके पाले-पोसे गुटों के हमलों तथा होर्मुज जलमार्ग एवं लाल सागर की सुरक्षा को लेकर उपजी चिंताओं ने इस क्षेत्र की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्थाओं में विसंगतियों को उजागर किया है। जहां तक इस समझौते का प्रश्न है तो तीनों हस्ताक्षरकर्ता देश एक-दूसरे की सैन्य एवं आर्थिक ताकतों को परस्पर क्षमताओं से संतुलित करते हैं। सऊदी अरब की शक्ति उसकी आर्थिक समृद्धि, ऊर्जा प्रभाव और भौगोलिक स्थिति है तो तुर्किये की ताकत उसकी नाटो सदस्यता एवं निरंतर उन्नत हो रहा रक्षा उद्योग है, जबकि पाकिस्तान के साथ भारी-भरकम सैन्य बल, परमाणु क्षमता और खाड़ी देशों में दीर्घकालिक सैन्य प्रशिक्षण एवं सुरक्षा सहयोग के अनुभव जैसे पहलू जुड़े हुए हैं। क्षमताओं का यह संयोजन इस समझौते को व्यावहारिक और रणनीतिक उपयोगिता प्रदान करता है। सऊदी अरब का वित्तीय सहयोग तुर्किये की रक्षा तकनीकों को संबल दे सकता है तो पाकिस्तान सैन्य शक्ति, प्रशिक्षण और तकनीकी विशेषज्ञता मुहैया करा सकता है। ऐसे में नाटो सरीखी किसी औपचारिक सामरिक संरचना का स्वरूप लिए बिना ही यह व्यवस्था चरणबद्ध रूप से एक एकीकृत सुरक्षा तंत्र को आकार तो दे ही सकती है। इस घटनाक्रम में भारत के लिए यह सवाल कोई मायने नहीं रखता कि क्या यह गठजोड़ %सुन्नी नाटो% बनेगा या नहीं, क्योंकि ऐसी किसी पहचान से तो ये तीनों देश ही इन्कार कर रहे हैं। भारत के संदर्भ में यही सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या इसकी आड़ में पाकिस्तान को अपने नापाक मंसूबे सिरे चढ़ाने को कोई गुंजाइश तो नहीं मिल जाएगी? पाकिस्तान को इस समझौते से काफी लाभ होने की उम्मीद है। उसकी भागीदारी न केवल इस्लामाबाद को खाड़ी क्षेत्र के सुरक्षा ढांचे में मजबूती से स्थापित कर सकती है, बल्कि उसे एक ऐसा मंच भी प्रदान करेगी जहां से वह स्वयं को केवल एक दक्षिण एशियाई सैन्य शक्ति से परे एक बड़े वैश्विक खिलाड़ी के रूप में पेश कर सके। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं कि भारत-पाकिस्तान सैन्य टकराव में सऊदी अरब या तुर्किये सीधे दखल देंगे। उनके अपने राष्ट्रीय हित ही बहुत जटिल हैं। तुर्किये को ईरान, यूरोप, खाड़ी और दक्षिण एशिया के साथ अपने समीकरणों को संतुलित रखना पड़ता है तो सऊदी अरब के भारत के साथ प्रगाढ़ आर्थिक एवं रणनीतिक रिश्ते हैं, जिनमें पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रगाढ़ता और बढ़ी है। ऐसे में इसके कोई आसार नहीं दिखते कि सऊदी अरब इस समझौते की आड़ में पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध कोई षड्यंत्र करने की अनुमति प्रदान करे। अब जब यह समझौता हो गया है तो भारत को चाहिए कि वह सऊदी के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाए ताकि खाड़ी क्षेत्र में पाकिस्तान की वजह से भारत की स्थिति किसी भी प्रकार से कमजोर न हो। खाड़ी क्षेत्र भारत के लिए केवल ऊर्जा की दृष्टि से ही अहम नहीं, बल्कि व्यापार, निवेश के साथ ही वहां रह रहे भारतवंशियों के लिहाज से भी बेहद अहम है। कनेक्टिविटी से जुड़ी भारत की आकांक्षाएं भी एक बड़ी हद तक इस क्षेत्र पर निर्भर हैं। इसके साथ ही भारत को तुर्किये द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य तकनीक एवं हथियारों की आपूर्ति और सऊदी अरब के वित्तीय समर्थन पर ध्यान रखना होगा। विशेष रूप से यह देखते हुए जब इसमें दक्षिण एशिया के पारंपरिक सैन्य शक्ति संतुलन बिगड़ने का जोखिम हो। भारत को अपनी रणनीतिक गतिशीलता भी कायम रखनी होगी। सऊदी अरब, यूएई, ईरान और इजरायल के साथ एक साथ संतुलित रिश्ते बनाए रखना हमारी बहुत बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि है, जिसे क्षेत्रीय गुटबाजी के चक्कर में दांव पर नहीं लगाया जाना चाहिए। भारत को अपनी रक्षा-औद्योगिक एवं तकनीकी क्षमताओं को भी विस्तार देना होगा। समग्रता में देखें तो मक्का समझौता न तो भारत-विरोधी खेमेबंदी है और न ही इससे पश्चिम एशिया में एकाएक कोई नया सैन्य गुट वजूद में आ गया है। इसका तात्कालिक उद्देश्य क्षेत्रीय अस्थिरता और भावी सुरक्षा परिदृश्य के अनिश्चित बादलों के बीच तीनों देशों को एक-दूसरे का रणनीतिक सुरक्षा-कवच मुहैया कराना है। जबकि भारत के लिए यह समझौता खाड़ी क्षेत्र के बदलते सुरक्षा परिदृश्य को पूरी गंभीरता से लेने की आवश्यकता को ही रेखांकित करता है। इस संदर्भ में भारत को न तो हड़बड़ाने की जरूरत है और न ही लापरवाह होने की। भारत को इतना ही करना है कि वह सऊदी अरब और खाड़ी देशों से संबंध और मजबूत करे, पाकिस्तान-तुर्किये सामरिक जुगलबंदी पर नजर रखे, समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही क्षेत्र के विरोधी खेमों से एक साथ संवाद साधने की अपनी क्षमता और बढ़ाए।

जेन-जी के सपनों को मिले पंख

मनु त्यागी

लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने युवा पीढ़ी यानी जेन-जी और जेन-अल्फा से सीधा संवाद किया। सरकार की नीतिगत दिशा स्पष्ट है-देश को डिजिटल, तकनीकी और मैन्यूफैक्चरिंग महाशक्ति बनाना। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मुफ्त ट्रेनिंग, डाटा सेंटर, क्रिटिकल मिनरल्स की खोज और सेमीकंडक्टर चिप प्लांट्स जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में भारी निवेश किया जा रहा है। सरकार का यह दीर्घकालिक सोच ‘विकसित भारत 2047’ के सपनों को पंख लगाने वाला है, लेकिन इस चमकदार तकनीकी भविष्य के सिक्के का एक दूसरा और बेहद स्याह पहलू भी है, जो आज देश की सड़कों पर युवाओं के आक्रोश के रूप में बार-बार दिखाई दे रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर और एआइ हब बनाने के प्रयास ऐतिहासिक हैं। सरकार चिप प्लांट्स और एआइ इकोसिस्टम के लिए लाखों करोड़ रुपये खर्च कर रही है। नीति-निर्माताओं का मानना है कि इन आधुनिक उद्योगों से देश में लाखों ‘हाई-एंड’ नौकरियां पैदा होंगी, लेकिन इस तथ्यात्मक सच से भी मुंह नहीं फेरा जा सकता कि ये उद्योग अत्यधिक पूंजी-गहन हैं, न कि श्रम-गहन। एक सेमीकंडक्टर प्लांट में अरबों रुपये का निवेश होता है, लेकिन वहां प्रत्यक्ष रोजगार कुछ हजार सुपर-स्पेशलाइज्ड इंजीनियरों को ही मिलता है। ऐसे में सवाल उठता है कि देश में सामान्य स्नातक पास फौज का क्या होगा? जो हर साल डिग्री लेकर रोजगार के बाजार की कतार में खड़ी हो रही है। आंकड़ों के आईने में शिक्षित बेरोजगारी का सच- आर्थिक मोर्चे पर युवाओं की स्थिति को समझने के लिए सरकारी और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के आंकड़े आंखें खोलने वाले हैं। इंडिया स्किल्स की एक रिपोर्ट बताती है कि कालेजों से निकलने वाले 50 प्रतिशत से अधिक युवा आज भी उद्योगों की तात्कालिक जरूरतों के हिसाब से रोजगार योग्य नहीं हैं। यानी कहीं न कहीं हमारे शैक्षणिक संस्थानों और वहां की शिक्षा प्रणाली में विसंगतियां हैं।जेन-जी और जेन-अल्फा युवाओं में बढ़ रहे असंतोष और उनके सड़कों पर उतरने की सबसे बड़ी और तात्कालिक वजह घरों में अभिभावकों के सपनों से जन्म लेने वाली लालसा और इंटरनेट मीडिया की होड़ तो है ही, इसके लिए कहीं न कहीं देश की चरमराई परीक्षा प्रणाली भी बराबर की दोषी है। पेपर लीक जैसी विसंगतियां इन युवाओं की बेचैनी स्वाभाविक रूप से बढ़ाती हैं। एक विश्लेषण के मुताबिक, पिछले पांच वर्षों में देश के 15 से अधिक राज्यों में 40 से ज्यादा बड़ी सरकारी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हुए हैं। नीट-यूजी, यूजीसी-नेट और विभिन्न राज्यों की सिपाही एवं प्रशासनिक भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधलियों ने देश के लगभग 1.5 करोड़ से अधिक युवाओं को कहीं न कहीं मानसिक तनाव तो दिया ही है, शैक्षणिक प्रणाली के प्रति उनके विश्वास को भी क्षति पहुंचाई है। यदि यह व्यवस्था ठीक होती, तो इस बड़े तबके के बीच असंतोष की चिंगारी इतनी गहरी नहीं होती और इसका लाभ उठाने वाले राजनीतिक दलों को बैठे-बिठाए अवसर नहीं मिलता। पेपर लीक होना, फिर परीक्षा का रद होना,

अदालती मुकदमेबाजी और दोबारा जांच के इस चक्रव्यूह में युवाओं की उत्पादक उम्र के स्वर्णिम वर्ष व्यर्थ हो रहे हैं। सरकार ने संसद में ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026’ पारित कर पेपर लीक के खिलाफ पांच करोड़ रुपये तक के जुर्माने और 10 वर्ष तक की जेल का प्रविधान किया है, लेकिन कानून केवल कागजी ढाल नहीं हो सकते, उन्हें जमीन पर बेहद कड़ाई से लागू करना होगा। ‘विकसित भारत’ का जो रास्ता सेमीकंडक्टर और एआइ की आधुनिक प्रयोगशालाओं से होकर गुजरता है, उसकी पहली सीढ़ी परीक्षा केंद्रों की शुचिता और पारदर्शिता से ही शुरू होती है। कोचिंग के भंवर से निकल ही बनेगा भविष्य- पीएम मोदी का संदेश है कि भारत का युवा अब केवल पारंपरिक सरकारी नौकरियों या डिग्रियों की अंधी दौड़ में अपना जीवन बर्बाद नहीं करेगा। सरकार की नई नीतियां जैसे ‘पीएम इंटर्नशिप योजना’ और कौशल विकास के नए अवसर, सीधे तौर पर उस ‘कोचिंग संस्कृति’ की जड़ों पर प्रहार करती हैं, जिसने दशकों से देश के युवाओं को बंधक बना रखा है। निश्चित ही, ये घोषणाएं उम्मीद जगाती हैं कि अब अरबों रुपये के इस कोचिंग बाजार को मात मिलेगी और देश का युवा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। कोचिंग के बाजार ने समाज को किस कदर प्रभावित किया है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कोचिंग संस्थानों ने आज देश में एक समानांतर और अनियंत्रित साम्राज्य खड़ा कर लिया है। इसने हमारे सामाजिक ताने-बाने को भी बहुत गहरे जख्म दिए हैं। आज एक बच्चे का बचपन 10वीं या 12वीं कक्षा में नहीं, बल्कि छठी और सातवीं कक्षा से ही कोचिंग के भंवर में फंस जाता है। पहले 10वीं-12वीं तक छात्र वर्ग का बड़ा तबका ट्यूशन या कोचिंग की शक्ल तक नहीं देखता था’ लेकिन बीते एक दशक में यह परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका है। अब कोचिंग एक स्टेटस सिंबल बन गई है। कोचिंग संस्थान छात्रों को इंसान नहीं, बल्कि केवल ‘रैंक’ और ‘रोल नंबर’ के रूप में देखने लगे हैं। इस माहौल में पला-बढ़ा युवा समाज के प्रति संवेदनशील होने के बजाय धीरे-धीरे अधिक आत्मकेंद्रित और रोबोटिक होता जा रहा है। कोचिंग के इस बाजार को खाद-पानी कहीं और से नहीं, बल्कि माता-पिता की अधूरी आकांक्षाओं और सामाजिक दिखावे से मिलता है। आज बच्चे की शिक्षा उसकी रुचि के अनुसार नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि शर्मा जी या वर्मा जी के बेटे ने कौन-सा कोर्स चुना है। हर साल केवल एक से दो प्रतिशत बच्चों का चयन ही आइआइटी, एम्स या यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में हो पाता है। शेष 98 प्रतिशत युवा खुद को ‘नाकाम’ मानने लगते हैं। एक सच इस समाज को समझना होगा कि हर बच्चा आइंस्टीन या सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकता।

जिंदगी में कोई भी सफलता एक दिन में नहीं मिलती। क्रिकेट की तरह जीवन भी लंबी पारी का खेल है। दिन का खेल खत्म होने पर नाबाद बल्लेबाज पवेलियन लौटता जरूर है, लेकिन उसके मन में अगली पारी के रन और बेहतर प्रदर्शन की तैयारी होती है। आज के युवा भी जिंदगी की ऐसी ही पारी खेल रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनके हाथ में बल्ले के बजाय स्मार्टफोन है और सामने का स्कोरबोर्ड रन नहीं, बल्कि लाइक्स, कमेंट, व्यूज और फालोअर्स गिनता है। इंटरनेट मीडिया ने युवाओं को अभिव्यक्ति का अभूतपूर्व मंच दिया है। प्रतिभा को पहचान मिली है, सूचनाओं तक पहुंच आसान हुई है और दुनिया से जुड़ने के अवसर बढ़े हैं। समस्या तब शुरू होती है जब आभासी दुनिया का स्कोर ही सफलता का पैमाना बन जाता है। कितने फालोअर्स हैं, कितने लाइक्स मिले, रील कितनी वायरल हुई-इन सवालों के बीच यह सवाल पीछे छूट जाता है कि व्यक्ति ने वास्तविक जीवन में कितना सीखा, कितना बनाया और समाज के लिए कितना उपयोगी साबित हुआ। युवा जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी समय, ऊर्जा, कल्पनाशीलता और सीखने की क्षमता है। यदि इनका बड़ा हिस्सा केवल डिजिटल लोकप्रियता हासिल करने में खर्च हो रहा है, तो हमें अपने स्कोरबोर्ड को नए सिरे से देखने की जरूरत है। असली स्कोर यह होना चाहिए कि कितनी किताबें पढ़ीं, कितने कौशल सीखे, कितनी चुनौतियों का सामना किया, कितने लोगों की मदद की और अपने भविष्य की नींव कितनी मजबूत की। भारत के लिए यह सवाल और महत्वपूर्ण है। देश की करीब आधी आबादी 29 वर्ष से कम उम्र की है। आने वाले दशकों में कामकाजी उम्र की आबादी और बढ़ेगी। यह भारत के लिए असाधारण जनसांख्यिकीय अवसर है, लेकिन युवा आबादी अपने आप जनसांख्यिकीय लाभांश नहीं बन जाती। इसके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, निष्पक्ष परीक्षाएं, रोजगार के अवसर, कौशल विकास, स्वतंत्र सोच और सुरक्षित सामाजिक वातावरण जरूरी हैं। आज के युवा केवल नौकरी नहीं, सम्मानजनक अवसर और अपनी प्रतिभा को साबित करने का मंच चाहते हैं। उनकी बेचैनी को समझना, उनके सवालों को सुनना और उनके सपनों को अवसर देना सरकार की ही नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। विश्वविद्यालय यदि स्वतंत्र विचार के केंद्र नहीं रहेंगे, परीक्षाओं पर भरोसा कमजोर होगा और रोजगार अवसर के बजाय विशेषाधिकार का माध्यम बन जाएगा, तो हमारी युवा शक्ति निराशा में बदल सकती है। 2047 का विकसित और स्वर्णिम भारत केवल हाई-टेक नीतियों, एआइ या आधुनिक बुनियादी ढांचे से नहीं बनेगा। उसे बनाने वाले आज के युवा होंगे। इसलिए जरूरी है कि उनके हाथ में स्मार्टफोन के साथ किताब भी हो, रील के साथ वास्तविक कौशल भी हो और फालोअर्स के साथ अपना स्वतंत्र विचार भी। याद रखना होगा-कोई भी टीम केवल स्कोरबोर्ड देखकर मैच नहीं जीतती। जीत के लिए ड्रेसिंग रूम में प्रतिभाओं की अगली कतार तैयार करनी पड़ती है। भारत का असली स्कोर भी लाइक्स और फालोअर्स में नहीं, बल्कि सक्षम, संवेदनशील, स्वतंत्र और आत्मविश्वासी युवाओं में दर्ज होगा।

संवैधानिक बराबरी बनाम सार्वजनिक बयान

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी अपने ही देश की हिंदू आबादी को लेकर दिए बयान के बाद विवादों में घिर गए हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह से जुड़े एक कार्यक्रम में भारत और पाकिस्तान की तुलना करते हुए जरदारी ने पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को लेकर ऐसी टिप्पणी की, जिस पर भारत में तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। मशहूर लेखक और गीतकार जावेद अख्तर ने जरदारी के बयान पर सीधे निशाना साधते हुए उनके पुराने चर्चित उपनाम ‘मिस्टर टेन परसेंट’ का जिक्र किया।

‘हम हिंदुओं को सहन करते हैं’

जरदारी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को लेकर दोनों देशों की सोच अलग है। उनके अनुसार भारत ‘अखंड भारत’ की विचारधारा रखता है, जबकि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है। इसी संदर्भ में पाकिस्तान की हिंदू आबादी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां मुसलमान 3-4 प्रतिशत हिंदू आबादी को ‘सहन’ करते हैं। जरदारी ने इसके साथ दावा किया कि पाकिस्तान में हिंदू उतने ही स्वतंत्र और सुरक्षित हैं, जितने वे कहीं और हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू भारत की तुलना में पाकिस्तान के साथ रहना अधिक पसंद करेंगे। यही वह टिप्पणी है जिसने विवाद को जन्म दिया है। आलोचकों का कहना है कि किसी देश के राष्ट्रपति द्वारा अपने ही नागरिकों के लिए ‘सहन करने’ जैसी भाषा का इस्तेमाल संवैधानिक बराबरी की भावना पर सवाल खड़ा करता है। नागरिक अधिकार किसी समुदाय पर बहुसंख्यक समाज की कृपा या सहनशीलता पर निर्भर नहीं हो सकते।

जरदारी के बयान को लेकर सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की वास्तविक स्थिति और उनके अधिकारों को लेकर उठ रहा है। पाकिस्तान की ओर से आधिकारिक स्तर पर समय-समय पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और समान अधिकारों की बात कही जाती रही है। अगस्त 2025 में अल्पसंख्यक दिवस के अवसर पर जरदारी ने भी संविधान के तहत सभी नागरिकों को समान अधिकार देने और धार्मिक भेदभाव के खिलाफ खड़े होने की प्रतिबद्धता जताई थी। ऐसे में उनके हालिया बयान को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है कि संवैधानिक बराबरी की बात

और सार्वजनिक मंच पर अल्पसंख्यक समुदाय को ‘सहन’ करने की टिप्पणी, दोनों में वास्तविक सोच कौन-सी है।

जावेद अख्तर ने पुराने उपनाम से साधा निशाना

जरदारी के बयान पर जावेद अख्तर ने सामाजिक माध्यम पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने जरदारी के हिंदुओं की 3-4 प्रतिशत आबादी को ‘सहन’ करने वाले बयान को उनके पुराने उपनाम ‘मिस्टर टेन परसेंट’ से जोड़ दिया। अख्तर ने व्यंग्य करते हुए कहा कि वह समझ सकते हैं कि जरदारी हमेशा से उन लोगों के प्रति असंवेदनशील रहे हैं जो ‘10 प्रतिशत से कम’ हैं। उनका यह तंज सीधे तौर पर जरदारी के पुराने उपनाम और उनके वर्तमान बयान को जोड़ता है। अख्तर की टिप्पणी इसलिए भी चर्चा में आ गई क्योंकि उन्होंने जरदारी के बयान में इस्तेमाल किए गए प्रतिशत को ही उनके पुराने उपनाम के संदर्भ से जोड़कर राजनीतिक व्यंग्य का रूप दे दिया।

‘मिस्टर टेन परसेंट’ से जुड़ा पुराना विवाद

आसिफ अली जरदारी के साथ ‘मिस्टर टेन परसेंट’ उपनाम लंबे समय से जुड़ा रहा है। यह उपनाम उन पुराने भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित रहा, जिनमें उन पर सरकारी परियोजनाओं और कारोबारी सौदों में 10 प्रतिशत कमीशन मांगने के आरोप लगाए गए थे। जरदारी इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं।जावेद अख्तर ने इसी पुराने राजनीतिक संदर्भ को मौजूदा बयान के साथ जोड़कर जरदारी की आलोचना की। इस तरह उनकी प्रतिक्रिया केवल हिंदुओं के संबंध में इस्तेमाल किए गए शब्द पर आपत्ति तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने जरदारी के पुराने राजनीतिक विवाद को भी निशाने पर ले लिया।

पाकिस्तान की नीतियों पर पहले भी बोल चुके हैं अख्तर

जावेद अख्तर इससे पहले भी पाकिस्तान की नीतियों और भारत-पाकिस्तान संबंधों को लेकर खुलकर अपनी राय रखते रहे हैं। पिछले वर्ष मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि भारत ने पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के लिए सांस्कृतिक और दूसरे स्तरों पर प्रयास किए, लेकिन पाकिस्तान की ओर से रिश्ते सुधारने के लिए ठोस प्रयास नहीं हुए। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद और आतंकियों को पनाह देने के मुद्दे पर भी पाकिस्तान की आलोचना की थी। ऐसे में जरदारी के ताजा बयान पर उनकी प्रतिक्रिया को उनके पुराने रुख के क्रम में देखा जा रहा है।

सवाल सिर्फ एक शब्द का नहीं

जरदारी के बयान पर उठे विवाद का मूल सवाल केवल ‘सहन’ शब्द तक सीमित नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि किसी देश में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों को किस नजरिए से देखा जाता है। यदि किसी समुदाय को उसके धर्म के कारण बहुसंख्यक आबादी की सहनशीलता के आधार पर सुरक्षित या स्वतंत्र बताया जाता है, तो समान नागरिक अधिकारों की अवधारणा कमजोर पड़ती है।

पहनावा निजी पसंद, समाज को हस्तक्षेप का हक नहीं

इसमें कोई दोराय नहीं कि देश को आजादी मिलने के बाद बीते करीब आठ दशक का सफर जहां बहुस्तरीय विकास का जीवंत उदाहरण है, वहीं इस दौरान लोगों ने बहुत सारे उतार-चढ़ाव भी देखे। मगर इस सबके बीच एक संकल्प कायम रहा कि जिन तूफानों और मुश्किलों का सामना करके देश ने स्वतंत्रता हासिल की थी, उसकी गरिमा को कायम रखना और भविष्य को ज्यादा बेहतर बनाना सभी का दायित्व है। इसमें आमतौर पर सभी नागरिकों ने अपने स्तर पर अपनी सीमा में हर संभव योगदान दिया है और इसे कर्तव्य की तरह निभाया है। यही वजह है कि हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर आजादी के आंदोलन को याद करते हुए देश के पास संतोष और उल्लास के साथ न केवल एक सुनहरे भविष्य का सपना होता है, बल्कि उसे जमीन पर उतारने का हौसला भी दिखता है।

आबादी के ज्यादातर हिस्से के पास विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए अलग-अलग दौर की सरकारों ने जिस स्तर पर काम किया, उसे बहुत जटिल संघर्षों के बाद मिली स्वतंत्रता की गरिमा और सपने को नया आयाम देने के प्रयासों के तौर पर देखा जा सकता है। यों देश की उपलब्धियों को आजादी की लड़ाई के नायकों की भूमिका के आईने में देखना स्वाभाविक ही है, लेकिन हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के मौके पर संघर्ष की संवेदना को महसूस करने की अपनी अहमियत है। इस वर्ष भी यह उत्साह देश के अलग-अलग राज्यों में हर जगह दिखा। जाहिर है, इस

अवसर पर जहां अतीत की उपलब्धियों को याद करना एक औपचारिक, लेकिन संवेदना से जुड़ा अध्याय है, वहीं भविष्य की बेहतरी के संकल्प भी जरूरी हिस्सा हैं। इसी संदर्भ में दिल्ली में लालकिले से प्रधानमंत्री ने भी एक बार फिर वक्त के सुनहरे अध्यायों को याद करते हुए देश को एक बेहतर भविष्य की दिशा में आगे ले जाने का संकल्प दोहराया। उनकी इस बात का अपना महत्त्व है कि देश के विकास के लिए बड़े सपने सोच का विस्तार करते हैं और दृढ़ संकल्प होने पर कठिनाइयों और आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने की सामर्थ्य अपने आप सामने आती है। उन्होंने महिलाओं, युवाओं, किसानों, गरीब और मध्यवर्ग के परिवारों को साथ लेकर 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प को दोहराया। विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए तैंतीस फीसद आरक्षण लागू करने के लिए सभी राजनीतिक दलों का आह्वान करने के साथ-साथ उन्होंने विकसित भारत बनाने के लिए ‘शक्ति की सप्तधारा’ का दृष्टिकोण भी साझा किया। दरअसल, यह देश की आत्मा में बसे उस जीवट का संकेत है, जिसका उदाहरण समय-समय पर दुनिया ने देखा है। यह सही है कि आज भी देश के सामने विकास की कसौटियों के समांतर अनेक जटिलताएं और चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं, लेकिन इन सबके बीच सामान्य स्थितियों से लेकर बेहद संवेदनशील और संकट जैसे हालात में भी लोगों ने धीरज के साथ देश की गति को बनाए रखने में अपना योगदान दिया है, जो वक्त के दस्तावेज में दर्ज होता रहा है। हालांकि आज भी सीमा पार और कई बार आंतरिक मोर्चों से मिलती चुनौतियां नई रणनीति के तकाजे की जरूरत को रेखांकित करती रही हैं, लेकिन देश ने अपना सफर जारी रखा है। यह बेवजह नहीं है कि आधुनिक तकनीक और दुर्लभ खनिजों के मामले में आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। इसलिए यह उम्मीद स्वाभाविक है कि आजादी के बाद अब तक देश में जो मजबूत नींव तैयार हुई है, उस पर विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। हम अक्सर सुंदरता की परिभाषा बड़ी चीजों, असाधारण चिह्नों और भव्य दृश्यों से जोड़ लेते हैं। चमकीली रोशनी से सजी इमारतें, महंगे पोशाक-परिधान और सोशल मीडिया पर खूब प्रचारित होने वाली तस्वीरें- ये सभी मन में सुंदरता का एक विशेष और ऊंचा मानक स्थापित कर देते हैं।

वंदे मातरम् पर विवाद

स्वतंत्रता दिवस समारोह पर अपने मुख्यालय में संपूर्ण वंदे मातरम् के गायन को लेकर जो विवाद पैदा हुआ, उसके लिए कांग्रेस अपने अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकती। कांग्रेस कुछ भी सफाई दे, यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि उसे वंदे मातरम् के संपूर्ण गायन की नई परिपाटी रास नहीं आई। गत दिवस गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह सोनिया गांधी की ओर से कथित तौर पर वंदे मातरम् के गायन को रोके जाने पर कांग्रेस से माफी की मांग की, उससे यही लगता है कि कांग्रेस ने जाने-अनजाने भाजपा के हाथ में एक मुद्दा थमा दिया। यह विवाद आसानी से थमने वाला नहीं, इसका संकेत इससे भी मिलता है कि बंकिम चंद्र के वंशज ने भी सोनिया गांधी से माफी की मांग कर दी। वंदे मातरम् को लेकर कोई पहली बार विवाद नहीं खड़ा हुआ। इस राष्ट्रीय गीत को लेकर रह-रहकर विवाद का विषय बनाने की कोशिश होती ही रही है। हाल में जब वंदे मातरम् के डेढ़ सौ साल पूरे होने पर मोदी सरकार ने उसके सभी छंद गाए जाने को अनिवार्य बनाया तब भी कांग्रेस ने उस पर आपत्ति जताई थी। इसके उपरांत जब राष्ट्रगान जन-गण-मन की तरह वंदे मातरम् को कानूनी संरक्षण देने संबंधी विधेयक पर संसद में चर्चा हुई तब भी कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों ने उसमें भाग लेने से इन्कार किया। 15 अगस्त के समारोह में केरल सरकार ने वंदे मातरम् के संपूर्ण गायन से इन्कार करके इस विवाद की जो शुरुआत की, उसे कांग्रेस मुख्यालय में हुए घटनाक्रम ने पूरा कर दिया। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर आयोजित समारोह में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने हिस्सा लेने से किनारा किया। उन्होंने ऐसा दूसरी बार किया। यह समझ आता है कि कांग्रेस को मोदी सरकार की रीति-नीति पसंद नहीं, लेकिन सरकार की रीति-नीति और राष्ट्रीय प्रतीकों में अंतर होता है। कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों की ओर से प्राय- इस अंतर को भुला दिया जाता है। इससे राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ-साथ राष्ट्रीयता की भावना का भी अनादर होता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया और जिसने अपने अधिवेशनों में वंदे मातरम् के गायन की परंपरा प्रारंभ की, वही उसे यथोचित सम्मान देने के लिए तैयार नहीं दिख रही है। मुस्लिम लीग के विरोध के बाद वंदे मातरम् के संपूर्ण गायन की जगह उसके दो छंद ही गाने की परंपरा शुरू हुई थी, लेकिन अब इस परंपरा को बदल कर वंदे मातरम् के सभी छंद गाए जाने का नियम बनाने पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

केंद्र ने नहीं बनाया 'मिसिंग लिंक' फिर भी मुझे झेलनी पड़ी आलोचना :गडकरी

एजेंसी। नई दिल्ली

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे के 'मिसिंग लिंक' हिस्से पर हुए भूस्खलन के बाद सोशल मीडिया पर हुई ट्रॉलिंग को लेकर अपना दर्द बयां किया है। सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित 'फेस्टिवल ऑफ थिंकर्स' व्याख्यान श्रृंखला में बोलते हुए गडकरी ने स्पष्ट किया कि इस परियोजना का निर्माण केंद्र सरकार ने नहीं, बल्कि महाराष्ट्र सरकार ने कराया है। फिर भी सोशल मीडिया पर उन्हें बिना वजह निशाना बनाया गया।

एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता और सोशल मीडिया ट्रॉलिंग पर गडकरी का क्या पक्ष था?

नितिन गडकरी ने कार्यक्रम में कहा:

- **27 साल पुरानी सड़क की मजबूती:** 'मैंने 27 साल पहले पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया था। आज भी इस सड़क की गुणवत्ता इतनी शानदार है कि इस पर एक भी गड्ढा नहीं है। हालांकि, इतने वर्षों बाद भी इस बेहतरीन सड़क की स्थिति के लिए मीडिया से कोई सराहना नहीं मिलती।'
- **सोशल मीडिया पर मिली बेवजह ट्रोलिंग:** 'लेकिन जब मिसिंग लिंक सेक्शन पर कोई समस्या आई, तो सोशल मीडिया पर मुझे ट्रोल किया गया और दोषी ठहराया गया। जबकि असलियत यह है कि मिसिंग लिंक का निर्माण महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया था।'
- **जवाबदेही तय करने का माध्यम:** इसके साथ ही गडकरी ने यह भी माना कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में गुणवत्ता बनाए रखने और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने में सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

'मिसिंग लिंक' प्रोजेक्ट में देरी और भूस्खलन की पूरी वजह क्या थी?

केंद्रीय मंत्री ने खुलासा किया कि वह एक्सप्रेसवे के मूल निर्माण के दौरान ही 'मिसिंग लिंक' बनाना चाहते थे, लेकिन उस समय वन विभाग से आवश्यक मंजूरी नहीं मिल सकी थी।

- **लागत और उद्देश्य:** लगभग 6,600 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बने इस मिसिंग लिंक का उद्घाटन 1 मई को किया गया था। ताकि पुणे और मुंबई के बीच यात्रा के समय को कम किया जा सके।
- **जुलाई का भूस्खलन:** जुलाई की शुरुआत में हुई भारी और लगातार बारिश के कारण इस हिस्से पर भूस्खलन हो गया, जिससे यातायात बाधित हुआ। इसके बाद विपक्षी नेताओं ने भी निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार की आलोचना की थी।

भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर केंद्रीय मंत्री का क्या विजन है?

नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को केवल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के बजाय 25 से 50 वर्षों के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ प्लान किया जाना चाहिए:

- **भविष्य की योजनाएं:** अस्थायी समाधानों पर निर्भर रहने के बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास दूरदर्शी होना चाहिए।
- **आर्थिक विकास में भूमिका:** मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर से उद्योग, व्यापार, पर्यटन और रोजगार को बड़ा बढ़ावा मिलता है। परिवहन लागत कम होने से भारतीय उद्योग वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे, जबकि बेहतर कनेक्टिविटी से किसानों की बाजारों तक पहुंच आसान होगी।
- **ऑटोमोबाइल सेक्टर का विस्तार:** गडकरी ने देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर की वृद्धि का श्रेय तकनीकी प्रगति, अनुसंधान, इलेक्ट्रिक वाहनों, वैकल्पिक ईंधनों और बायोफ्यूल्स को दिया।

पुणे शहर के लिए किन नई इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं का एलान किया गया?

अपने संबोधन के आखिर में गडकरी ने जानकारी दी कि आने वाले समय में पुणे शहर के लिए लगभग 60,000 करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की योजना बनाई गई है। इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को लागू करने के लिए नए और इनोवेटिव फाइनेंसिंग मॉडल्स को अपनाया जा रहा है।

एमपी के भिंड में दर्दनाक हादसा: यूपी के लखीमपुर लौटते वक्त पिकअप डंपर से टकराई, आठ मजदूरों की मौत और 25 घायल

एजेंसी। भिंड

भिंड में नेशनल हाईवे-719 पर सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। गोहद के छीमका गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप सामने से आ रहे डंपर से टकरा गई। पिकअप में ग्वालियर क्षेत्र से धान की रोपाई का काम पूरा कर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी लौट रहे मजदूर सवार थे। हादसे में आठ मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हुए हैं। गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है।

मवेशियों को बचाने के प्रयास में हुआ हादसा

हादसा सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात करीब एक बजे हुआ। पुलिस के मुताबिक, पिकअप की रफ्तार करीब 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा होने का अनुमान है। छीमका गांव के पास हाईवे पर कुछ गायें सड़क पर बैठी थीं। अचानक सामने आए मवेशियों को बचाने के प्रयास में पिकअप चालक ने वाहन मोड़ दिया और सामने से आ रहे डंपर से जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वाहन में सवार मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई। गोहद चौराहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को क्षतिग्रस्त वाहन से बाहर निकाला गया। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।

टू-लेन है भिंड से ग्वालियर-इटावा को जोड़ने वाला हाईवे

भिंड से ग्वालियर और उत्तर प्रदेश के इटावा को जोड़ने वाला 117 किलोमीटर का यह हाईवे आज भी मात्र टू-लेन है। बिना डिवाइडर वाली इस पतली सड़क पर दिन-रात भारी डंपरों और बालू-रेत के ओवरलोड वाहनों का अत्यधिक दबाव रहता है।

धान की रोपाई के बाद लखीमपुर लौट रहे थे मजदूर

बताया जा रहा है कि सभी मजदूर ग्वालियर क्षेत्र में धान की रोपाई का काम करने आए थे। काम पूरा होने के बाद वे पिकअप से अपने गांव लखीमपुर खीरी लौट रहे थे। लेकिन रात के सफर में छीमका गांव के पास उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। गोहद चौराहा थाना प्रभारी रामनरेश यादव के मुताबिक, हादसे में 8 मजदूरों की मौत हुई है, जबकि 25 लोग घायल हैं। गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है। मृतकों के शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजे गए हैं और मृतकों एवं घायलों की पहचान की जा रही है।

सड़क पर बैठी गायों को बचाने के प्रयास को हादसे की वजह

शुरुआती जांच में सड़क पर बैठी गायों को बचाने की कोशिश को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है। रात के समय तेज रफ्तार वाहनों के सामने अचानक मवेशी आने से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है।हादसे के बाद कुछ समय तक हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सामान्य कराया। फिलहाल पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों की पहचान और दुर्घटना की परिस्थितियों की विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है।

कागजों में सिमटा फोरलेन

एनएच-719 को फोरलेन बनाने की मांग को लेकर दंदरौआ धाम के संत समाज से लेकर स्थानीय युवाओं ने कई बड़े आंदोलन, चक्काजाम और ज्ञापन सौंपे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय और ह.ĥ्ड की बैठकों में फोरलेन को मंजूरी देने और टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के बड़े-बड़े दावे तो किए गए, लेकिन धरातल पर आज तक काम शुरू नहीं हो सका। नतीजतन, बिना डिवाइडर वाले इस खूनी हाईवे पर हर दिन मुसाफिर अपनी हथेली पर जान रखकर सफर करने को मजबूर हैं।

'अभिजीत दीपके हमारा अपना ही लड़का, बौद्ध है'

एजेंसी। नई दिल्ली

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि दीपके आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ता हैं। रिजिजू ने उनकी छात्र के रूप में पहचान पर भी सवाल किया। हालांकि, उन्होंने दीपके के लिए नरम रुख दिखाते हुए उन्हें अपना ही लड़का बताया। हाल ही में सीजेपी के बैनर तले जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन हुआ था। इसके चलते पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था।

अभिजीत दीपके और सीजेपी के आंदोलन पर क्या कहा?

रिजिजू ने समाचार एजेंसी एएनआई को इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने अभिजीत दीपके और उनके आंदोलन को लेकर सवाल उठाए। रिजिजू से जब छात्रों की शिक्षा क्षेत्र में सुधार से जुड़ी मांगों और जेन-जी आंदोलन पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने माना कि छात्रों की चिंताएं जायज हैं। हालांकि, उन्होंने दावा किया कि राजनीतिक दलों ने इस आंदोलन को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया है।

आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं दीपके: रिजिजू

युवाओं के बीच पहचान बना चुके अभिजीत दीपके का नाम लेते हुए रिजिजू ने कहा, लेकिन अभिजीत दीपके है वह हमारा अपना ही लड़का है, महाराष्ट्र से बौद्ध है। इसके बाद उन्होंने दीपके के छात्र होने पर सवाल उठाते हुए कहा, लेकिन वो तो आम आदमी का कार्यकर्ता है, वो तो आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। वो छात्र कैसे हो गया?

'छात्रों की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकते हैं दल'

रिजिजू ने विपक्षी दलों और खास तौर पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब वे राजनीतिक दल हार जाते हैं, तो वे छात्रों की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। ऐसा करना लोकतंत्र के लिए सही नहीं है।

आंदोलन के दौरान कानून-व्यवस्था पर क्या कहा?

उन्होंने यह भी कहा कि इतने बड़े प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाकर रखी और किसी व्यक्ति को खरोंच तक नहीं आई। रिजिजू ने दावा किया कि इसके बावजूद विपक्ष सरकार पर छात्रों के दमन की झूठी कहानी बनाने की कोशिश कर रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने अभिजीत दीपके को एनडीए में आने का दिया न्योता, कहा, अंबेडकर का सपना करें पूरा

एजेंसी। नई दिल्ली

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके को भाजपा के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) में शामिल होने का प्रस्ताव मिला है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि सीजेपी संयोजक को डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर का सपना पूरा करने के लिए उनकी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होने पर विचार करना चाहिए। दीपके ने अभी तक मंत्री के प्रस्ताव का कोई जवाब नहीं दिया है। सीजेपी नेता ने पहले भी चुनावी राजनीति में आने से इनकार कर दिया था। उनका कहना है कि लोगों का राजनीति और चुनाव प्रणाली से भरोसा उठ गया है।

अठावले ने क्या कहा?

पत्रकारों से बात करते हुए अठावले ने कहा कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके को डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर का सपना पूरा करने और साथ ही समाज व पार्टी को मजबूत बनाने के लिए उनकी पार्टी में शामिल होने पर विचार करना चाहिए। इस महीने की शुरुआत में, दीपके ने कहा था कि लोगों का राजनीति और चुनाव प्रणाली से भरोसा उठ गया है। उन्होंने कहा कि देश को किसी और राजनीतिक पार्टी के बजाय एक जन-आंदोलन की जरूरत है।

दीपके को लेकर क्या कहा?

बता दें कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा है। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि अभिजीत दीपके एक अंबेडकरवादी हैं। वह सक्रिय और युवा हैं। उन्हें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होने पर विचार करना चाहिए।' इसके साथ ही दीपके को राजनीति में शामिल होने का न्योता देते हुए अठावले ने कहा कि सरकार का मानना है कि गलत काम करने वालों को सजा मिलनी चाहिए।

लड़ाकू विमान से मिसाइल तक, भारत में बनेंगे 405 रक्षा उत्पाद

एजेंसी। नई दिल्ली

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश के रक्षा उत्पादन क्षेत्र को बड़ी मजबूती मिली है। रक्षा उत्पादन विभाग ने 405 रणनीतिक रूप से अहम रक्षा वस्तुओं की छठी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की है।

405 रक्षा उत्पादों में क्या-क्या शामिल?

इन 405 वस्तुओं का अनुमानित कारोबारी मूल्य करीब 3,070 करोड़ रुपए है। इनमें हेलिकॉप्टर से लेकर लड़ाकू विमान व बख्तरबंद प्लेटफॉर्म से जुड़े अहम उपकरण, मिसाइल व रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स, तटरक्षक बल और रक्षा उपक्रमों की वस्तुएं शामिल हैं। इन सभी वस्तुओं का अब देश में ही विकास और उत्पादन किया जाएगा। इससे आने वाले समय में इनके आयात पर निर्भरता कम होगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, नई सूची में 16 वस्तुएं भारतीय तटरक्षक बल और 389 वस्तुएं रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से जुड़ी हैं। यह सूची काफी व्यापक है। इसमें अलग-अलग हथियार प्रणालियों और रक्षा प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल होने वाले कल-पुर्जे, उप-प्रणालियां, उप-असेंबली, स्पेयर पार्ट्स, घटक व कच्चा माल शामिल है। इस सूची में सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए इस्तेमाल होने वाले कई अहम उपकरण शामिल हैं। वायु प्लेटफॉर्म में एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलिकॉप्टर, सुखोई-30 एमके आई, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एएल-31एफपी इंजन से जुड़े उत्पाद शामिल हैं।

टैंक और मिसाइलों का सामान भी देश में बनेगा

वहीं, बख्तरबंद प्लेटफॉर्म के लिए टी-72, टी-90 और बीएमपी-टू से जुड़े अहम उपकरण भी सूची में रखे गए हैं। सरकार ने कई अहम मिसाइल प्रणालियों से जुड़े सामानों को भी स्वदेशी तौर पर बनाने का फैसला किया है।

'प्राइवेट अस्पताल में कराएं इमरान खान की मेडिकल जांच', पाक सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

एजेंसी। इस्लामाबाद

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान को इलाज और स्वास्थ्य जांच के लिए निजी अस्पताल ले जाने का आदेश दिया है। अदालत ने यह निर्देश मंगलवार को इमरान खान की आंखों की बीमारी से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया। तीन सदस्यीय पीठ की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस शाहिद वहीद ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 73 वर्षीय इमरान खान को अगले कुछ दिनों में इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया जाए। अदालत ने कहा कि यह आदेश कैदी के मौलिक अधिकारों और उसकी सेहत एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिया गया है।

सरकारी अस्पताल के इलाज से संतुष्ट नहीं थे याचिकाकर्ता

इमरान खान की आंखों की बीमारी को लेकर दायर याचिकाओं में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वे सरकारी अस्पतालों में मिल रहे इलाज से संतुष्ट नहीं हैं और इमरान खान को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इमरान खान की आंखों की समस्या इस साल जनवरी के अंत में सामने आई थी। उन्हें दाहिनी आंख की सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन (सीआरवीओ) नाम की बीमारी हुई थी। इसके बाद उन्हें कई बार इस्लामाबाद स्थित पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (पीआईएमएस) ले जाया गया।

जेल प्रशासन ने कहा, आंखों की रोशनी में सुधार

अदालत में जेल प्रशासन की ओर से पेश रिपोर्ट में दावा किया गया कि इमरान खान का बीमारी सामने आने के बाद उचित इलाज कराया गया। उनका इलाज पीआईएमएस के नेत्र रोग विभाग के प्रमुख डॉ. मुहम्मद आरिफ खान और अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल, रावलपिंडी के विट्रियो-रेटिनल सर्जन डॉ. नदीम कुरैशी ने किया। रिपोर्ट में कहा गया कि इलाज के बाद इमरान खान की आंखों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है और उनकी दृष्टि लगभग सामान्य हो गई है। जेल अधिकारियों ने यह भी दावा किया कि इमरान खान को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जेल प्रशासन ने हर संभव प्रयास किया।

आरोपियों की पहचान ऑनलाइन जाहिर करने पर रोक की मांग, केंद्र और सोशल मीडिया कंपनियों को नोटिस

एजेंसी। नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र, सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा और एक्स को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस एक जनहित याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें पुलिस को ऐसे कंटेंट पोस्ट करने से रोकने के निर्देश देने की मांग की गई है, जिनसे आरोपियों की पहचान जाहिर होती हो या उन्हें अपमानजनक तरीके से दिखाया जाता हो।

याचिका में राज्यों को निर्देश देने की भी मांग

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने पीआईएल दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता हेमेंद्र पटेल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन की दलीलों पर गौर किया और केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किए। याचिका में राज्यों को निर्देश देने की मांग की गई कि वे अपने पुलिस सोशल मीडिया हैंडल से ऐसी पोस्ट तुरंत हटा दें, जिनमें आरोपियों के चेहरे या पहचान जाहिर होती हो या उन्हें अपमानजनक तरीके से दिखाया गया हो। याचिका में कहा गया, 'प्रतिवादी-राज्यों को निर्देश दिया जाए कि वे अपने-अपने पुलिस संगठनों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए उचित गाइडलाइंस बनाएं, खासकर ऐसे कंटेंट को अपलोड करने से रोकने के लिए जिनसे आरोपियों के चेहरे/पहचान जाहिर होती हो या उन्हें अपमानजनक तरीके से दिखाया जाता हो।'

आरोपियों को अपमानजनक तरीके से दिखाए जाने पर आपत्ति

याचिका में ऐसी तस्वीरों या वीडियो का जिक्र किया गया है जिनमें आरोपियों को हथकड़ी पहने, रस्सियों से बंधे, डंडों से पीटते, घुटनों के बल बैठे, घसीटे जाते या सीढ़ियों से नीचे खींचे जाते हुए दिखाया गया है। याचिका में राज्यों से यह भी मांग की गई है कि वे पुलिस द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए उचित गाइडलाइंस बनाएं, ताकि भविष्य में ऐसे कंटेंट की पोस्टिंग को रोका जा सके।

सोशल मीडिया कंपनियों को भी तय गाइडलाइंस बनाने की मांग

याचिका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मेटा और एक्स को भी निर्देश देने की मांग की गई है कि वे अपने प्लेटफॉर्म के लिए उचित पॉलिसी और यूजर गाइडलाइंस बनाएं। जिसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि ऐसा कोई कंटेंट पोस्ट न किया जाए जिससे आरोपियों की पहचान जाहिर होती हो या उन्हें अमानवीय, अपमानजनक या बेइज्जती भरे बर्ताव का शिकार होते हुए दिखाया जाता हो। इसमें यूजर द्वारा रिपोर्ट किए जाने पर ऐसे कंटेंट को तुरंत हटाने के लिए एक औपचारिक, पारदर्शी और व्यवस्थित तंत्र बनाने की भी मांग की गई है। इस मामले में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक और एक्स कॉर्प को प्रतिवादी बनाया गया है।

'पूरे देश में बदलेगा सिस्टम': छात्रों की हड़ताल खत्म होने पर राहुल ने जताई खुशी

एजेंसी। नई दिल्ली

झारखंड के छात्रों और राज्य सरकार के बीच सोमवार रात सहमति बन गई। अब इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि छात्रों ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। यह खबर सुनकर अच्छा लगा।

कांग्रेस नेता ने क्या कहा?

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा,'मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और झारखंड सरकार ने बातचीत का रास्ता चुना और समाधान निकाला। छात्रों ने संयम बरता और अपनी बात रखी। यही सही तरीका है, जब छात्र सवाल उठाएं, तो उन्हें जवाब मिलना चाहिए। हम देश के हर छात्र के साथ खड़े हैं। हम इस रिकवरी सिस्टम को पूरी तरह बदल देंगे। ताकि हर छात्र को अपनी मेहनत का पूरा फल मिले और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का अधिकार मिले। यह सिस्टम पूरे देश में बदलेगा। अब एक ऐसा ढांचा तैयार किया जाएगा जो छात्रों को आगे बढ़ाए। न कि उन्हें पीछे रोके।

कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर क्या आरोप लगाया?

इसके साथ ही कांग्रेस ने मंगलवार को मोदी सरकार पर जाति जनगणना को बाधित करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही पूछा कि 2027 की जनगणना में जाति चयन के लिए ड्रॉप-डाउन मेनू क्यों शामिल नहीं किया गया है। वहीं, केंद्र ने सितंबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय में अपने हलफनामे में इसकी सिफारिश की थी।

पुलिस की ज्यादती के आरोपों की जांच करेगी उच्च स्तरीय समिति

एजेंसी। नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की ज्यादती के आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाएगा। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान बनाए गए वीडियो फुटेज को उच्च स्तरीय समिति को सौंपने का निर्देश दिया जाएगा। यह समिति इन वीडियो की जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, यह उच्च स्तरीय समिति 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाए जाने के आरोपों की भी जांच करेगी। चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहन की पीठ बुधवार को आदेश जारी करेगी।

होर्मुज में जहाज पर हमला: इंजन रूम क्षतिग्रस्त, चालक दल का एक सदस्य हताहत

एजेंसी। दुबई

होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर निकल रहे एक जहाज को मंगलवार तड़के अज्ञात प्रोजेक्टाइल ने निशाना बनाया। ब्रिटिश सेना के यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस केंद्र के अनुसार, हमले में जहाज के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा और चालक दल का एक सदस्य हताहत हुआ। हमले की तत्काल किसी संगठन या देश ने जिम्मेदारी नहीं ली है। घटना ने एक बार फिर इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से जहाजों की आवाजाही को लेकर सुरक्षा चिंताएं बढ़ा दी हैं।

क्या जहाज पर हमले में किसी की मौत हुई?

UKMTO ने जहाज या उसके माल से जुड़ी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। यह भी तत्काल स्पष्ट नहीं हो सका कि चालक दल का सदस्य हमले में मारा गया है या घायल हुआ है। एजेंसी ने बताया कि ओमान का तटरक्षक बल जहाज के अन्य चालक दल के सदस्यों की मदद कर रहा है। घटना की जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि, अब तक इस घटना के कारण समुद्र में किसी तरह के पर्यावरणीय नुकसान की सूचना नहीं मिली है।

क्यों अहम है होर्मुज जलडमरूमध्य?

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। युद्ध से पहले दुनिया के कुल कारोबार वाले तेल का करीब पांचवां हिस्सा इस मार्ग से होकर गुजरता था। ऐसे में इस रास्ते पर जहाजों की आवाजाही बाधित होने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और तेल बाजार पर असर पड़ने की आशंका रहती है। ईरान ने 28 फरवरी को इस्राइल और अमेरिका के हमलों के बाद इस जलडमरूमध्य को प्रभावी रूप से बंद कर दिया था। अमेरिका भी फिलहाल इस मार्ग से ईरानी जहाजों की आवाजाही को रोकने के लिए नाकेबंदी कर रहा है।

क्या ईरान और ओमान के बीच हो रही है बातचीत?

अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फिलहाल ठप पड़ी हुई है। इसी बीच ईरान, ओमान के साथ अलग से होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों के प्रबंधन को लेकर बातचीत कर रहा है। ईरान ने सोमवार को कहा था कि दोनों पक्ष एक संयुक्त बयान जारी करने की योजना के अंतिम विवरण पर काम कर रहे हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ओमान को लेकर कथित तौर पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के पत्रकार ट्रे यिंग्स्ट से फोन पर बातचीत के दौरान कथित तौर पर चेतावनी दी कि यदि ओमान रास्ते में बाधा बनता है तो अमेरिका उस पर हमला कर सकता है।

आयुर्वेदिक औषधि की आड़ में डोडा-पोस्त की तस्करी

10 क्विंटल से ज्यादा की खेप पकड़ी, नींबू-संतरे के छिलकों के नीचे छिपा रखी थी; आरोपी अरेस्ट

अजमेर। अजमेर जिला स्पेशल टीम (डीएसटी) और गेगल थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक पिकअप से 10 क्विंटल 9.800 किलोग्राम डोडा-पोस्त बरमद किया है। पुलिस के अनुसार, जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 51 लाख 47 हजार रुपए है। इस कार्रवाई में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर तस्करी में इस्तेमाल पिकअप भी जब्त की है।

पुलिस के अनुसार डोडा-पोस्त की यह खेप मध्यप्रदेश के नीमच जिले के मोड़ी गांव से बीकानेर ले जाई जा रही थी। आरोपी की पहचान मध्यप्रदेश के नीमच जिले के मोडी गांव निवासी अमर सिंह मोगिया (29) के रूप में हुई है। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच पुष्कर थाना प्रभारी अशोक बिस्सु को सौंपी गई है।

कायड़ चौराहे पर मिली थी तस्करी की सूचना

गेगल थाना एसएचओ रोशनलाल के मुताबिक डीएसटी को कायड़ चौराहा से एक पिकअप में पुष्कर की तरफ भारी मात्रा में डोडा पोस्त भरकर ले जाने की सूचना मिली। इस पर डीएसटी और गेगल पुलिस की टीम ने नाकाबंदी की। चालक ने पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास किया और वाहन को विश्राम स्थली की ओर ले जाने का प्रयास किया।

नींबू-संतरों के छिलकों के पीछे छिपाया था

डीएसटी प्रभारी शंकर सिंह रावत के मुताबिक पिकअप वाहन को जब्त कर तस्करी के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने यह खेप नींबू संतरे के छिलकों के नीचे छिपा रखा था। तिरपाल को हटाकर देखा तो नींबू और संतरे के छिलके कट्टों में भरे मिले। इसे आयुर्वेदिक औषधि के लिए ले जाना बताया गया। ऊपर के पांच कट्टे हटाकर नीचे के कट्टे खोले गए तो पैकिंग पर श्री श्याम औषधि आयुर्वेदिक लिखा मिला। इन कट्टों में अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त भरा हुआ था। इस कार्रवाई में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो नीमच की टीम ने भी सहयोग किया।

नदबई में आज दिव्यांग सहायता उपकरण शिविर

ट्राई साइकिल, व्हीलचेयर का होगा रजिस्ट्रेशन, ये डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे

नदबई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 19 अगस्त को नगर पालिका नदबई में दिव्यांगजन सहायक उपकरण चिन्हीकरण शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर को लेकर विभाग की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शिविर में जरूरतमंद दिव्यांगजनों का चिन्हीकरण एवं रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।

जरूरत के अनुसार सहायक उपकरण के लिए करा सकेंगे पंजीयन

शिविर में ऐसे दिव्यांगजन, जिन्हें ट्राई साइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र सहित अन्य सहायक उपकरणों की आवश्यकता है, वे उपस्थित होकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। विभाग की ओर से पात्र दिव्यांगजनों का चिन्हीकरण कर आवश्यकतानुसार सहायक उपकरण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

ये दस्तावेज लाने होंगे : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शिविर में आने वाले दिव्यांगजन अपने साथ UDID कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, दिव्यांगता दर्शाता हुआ फोटो और आय प्रमाण पत्र लेकर उपस्थित हों। दस्तावेजों के आधार पर पात्रता संबंधी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

विभाग ने शुरू की तैयारियां

शिविर को लेकर विभागीय स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अधिकारियों ने अधिक से अधिक पात्र दिव्यांगजनों से शिविर में पहुंचकर अपना पंजीयन करवाने की अपील की है, ताकि जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजना के तहत सहायक उपकरण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी की जा सके। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शिविर का उद्देश्य जरूरतमंद दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए चिन्हीकृत करना है। पात्र दिव्यांगजन निर्धारित तिथि पर जरूरी दस्तावेजों के साथ नगर पालिका नदबई में पहुंचकर शिविर का लाभ ले सकते हैं।

पीपल्दा में किसानों की किसान न्याय क्रांति

ट्रैक्टर रैली से घेरा दीगोद उपखंड कार्यालय, जबरन अटैचमेंट रोकने का प्रशासन ने दिया आश्वासन

कोटा। पीपल्दा विधानसभा क्षेत्र के किसानों ने विधायक चेतन पटेल कोलाना के नेतृत्व में %किसान न्याय क्रांति% आंदोलन किया। यह प्रदर्शन विभिन्न समस्याओं और लंबित मांगों को लेकर आयोजित किया गया था। कोलाना गांव से एक विशाल ट्रैक्टर रैली शुरू हुई, जिसमें इटावा, खातौली सहित विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों से बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए।

मोटरसाइकिलों और ट्रैक्टरों का यह काफिला कई किलोमीटर तक फैला हुआ था। रैली दीगोद पहुंची, जहां किसानों ने उपखण्ड कार्यालय का घेराव कर जोरदार नारेबाजी की। इस आंदोलन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अखिल भारतीय किसान महासभा के जिलाध्यक्ष रामप्रसाद परालिया, जिला अध्यक्ष भानु प्रताप,उपमहापौर पवन मीणा,ब्लॉक अध्यक्ष ओमप्रकाश बैरवा,महेंद्र गुर्जर,हरिप्रकाश शर्मा सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे।

किसानों ने खाद की किल्लत, डीएपी-यूरिया के साथ जबरन अटैचमेंट, फसल बीमा क्लेम, स्मार्ट मीटर, इटावा मंडी के 102 किसानों के करीब 1.46 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान, तारबंदी व कृषि यंत्र सब्सिडी, कैटलशेड व शौचालय भुगतान तथा नरेगा मजदूरी के बकाए जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए।

दीगोद कार्यालय पहुंचने पर किसानों ने खाद के साथ जबरन अटैचमेंट के मुद्दे को सबसे प्रमुखता से उठाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें केवल आश्वासन नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने की आवश्यकता है। किसानों ने यह भी कहा कि जब तक प्रशासन जबरन अटैचमेंट रोकने की सार्वजनिक घोषणा नहीं करता, तब तक अन्य मांगों पर कोई वार्ता नहीं होगी।

किसानों के दबाव के बाद, प्रशासन ने मौके पर घोषणा की कि पीपल्दा क्षेत्र में डीएपी और यूरिया के साथ किसी भी प्रकार का जबरन अटैचमेंट नहीं किया जाएगा। साथ ही, किसानों को सरकारी दर पर खाद उपलब्ध कराने और कालाबाजारी रोकने का भी आश्वासन दिया गया। इस घोषणा के बाद, अन्य मांगों पर अधिकारियों के साथ सकारात्मक चर्चा हुई और उनके समाधान के लिए निर्धारित समय सीमा में भरोसा दिलाया गया। अंत में, विधायक चेतन पटेल कोलाना सहित किसान प्रतिनिधियों ने प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर वादाखिलाफी हुई, तो अगला आंदोलन कोटा कलेक्ट्रेट का घेराव कर किया जाएगा। प्रशासन के आश्वासनों के बाद किसानों का धरना समाप्त हो गया।

नाबालिग को भाभी का भाई भगा ले गया

4 महीने साथ रखा; रेप के दोषी को 20 साल की सजा

कोटा। कोटा में नाबालिग से रेप के करीब 4 साल पुराने मामले में पॉस्को कोर्ट क्रम-5 ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 22 वर्षीय दोषी युवक को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। घर से जेरोक्स (फोटोकॉपी) कराने निकली नाबालिग को दोषी युवक बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। इसके बाद करीब 4 महीने तक नाबालिग को भीलवाड़ा और बिजोलिया में अपने साथ रखकर दुष्कर्म किया था। एडवोकेट महेश चादवानी ने बताया- 4 अक्टूबर 2022 को पीड़िता के पिता ने ग्रामीण थाने में शिकायत दी थी। इसमें बताया कि मेरी 16 साल की बेटी 9वीं कक्षा में पढ़ती है। नाबालिग बेटी सुबह जेरोक्स कराने की कहकर घर से निकली थी। जो शाम तक वापस नहीं लौटी। रिश्तेदारों और आसपास तलाश करने पर भी उसका पता नहीं लगा। उन्हें शक था कि मेरी बहू का भाई मेरी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। बेटी आरोपी लड़के से फोन पर बात करती थी। आरोपी युवक का घर में आना-जाना था। आरोपी युवक ने ही फोन करके बेटी को बुलाया और भगा कर ले गया था।

18 गवाहों के बयान करवाए

शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पीड़िता को डिटेन कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 18 गवाह के बयान करवाए और 28 दस्तावेज पेश किए। फैसले में कोर्ट ने पीड़िता को 5 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि दिलाने के अनुशंसा की है।

लिखमीसर दिखनादा गांव में सर्व समाज की बैठक

तेजाजी और बजरंग बली महाराज के भव्य मंदिर निर्माण का लिया निर्णय

जसरासर। लिखमीसर दिखनादा गांव में सर्वसमाज ने एकता की मिसाल पेश करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों ने मिलकर वीर तेजाजी महाराज और वीर बजरंग बली महाराज के भव्य मंदिर निर्माण का फैसला किया है। इस बैठक में मेघवाल, सांसी, भार्गव, गवारिया, राजपूत, नायक, स्वामी, प्रजापत, लुहार, नाई, सोनी, ढाढी समाज के मौजिज लोग मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त, जाट समाज के डेलू, कूकना, भादू, तर्ड, खोड, बाना, रिन्टोड और ठोलिया गोत्रों के प्रतिनिधियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सर्वसमाज के लोगों ने इस मंदिर निर्माण को आपसी भाईचारे, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने वाला कदम बताया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि वीर तेजाजी महाराज सत्य, साहस और वचनबद्धता के प्रतीक हैं, जबकि बजरंग बली शक्ति, भक्ति, सेवा और समर्पण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस अवसर पर मंदिर निर्माण के लिए सामूहिक सहयोग का आह्वान किया गया।

गढ़ी बाजना में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़

एक आरोपी गिरफ्तार, दो फरार; अवैध हथियारों की सप्लाई करने आए थे

पटपरीपुरा (बयाना)। गढ़ी बाजना थाना क्षेत्र में पुलिस और अवैध हथियारों की सप्लाई करने आए बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि दो अन्य बदमाश पहाड़ी इलाके का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि तीन बदमाश इलाके में अवैध हथियारों की खेप पहुंचाने की फिराक में हैं। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने बारैठा बांध की पहाड़ी की पाल के पास घेराबंदी की।

खुद को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से बड़ी मात्रा में अवैध हथियार और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और फरार बदमाशों की तलाश में पहाड़ी क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया है।

ट्रैक्टर-ट्रॉली के गुप्त चैंबर में छिपाया 123 किलो डोडाचूरा

CBN ने पकड़ा, मध्यप्रदेश से बिजौलिया लाया जा रहा था

बिजौलिया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की चित्तौड़गढ़ सेल यूनिट ने बिजौलिया क्षेत्र में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने मध्यप्रदेश से आ रही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली से 123.630 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा बरामद किया। तस्करी के लिए डोडाचूरा को ट्रॉली के हाइड्रोलिक सिस्टम और ढांचे के बीच बने गुप्त चैंबर में छिपाया गया था। CBN ने ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया।

मुखबिर की सूचना पर शुरू की निगरानी

CBN टीम को सूचना मिली थी कि मध्यप्रदेश से एक ट्रैक्टर-ट्रॉली में मादक पदार्थ छिपाकर बिजौलिया क्षेत्र में लाया जा रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद चित्तौड़गढ़ सेल यूनिट ने भगवानपुरा-उमाजी का खेड़ा मार्ग पर निगरानी शुरू की। कुछ समय बाद मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिए की ट्रैक्टर-ट्रॉली वहां से गुजरती दिखाई दी। अधिकारियों ने वाहन को रुकवाकर तलाशी ली।

सामान्य जांच में नहीं मिला कोई सुराग : CBN अधिकारियों ने ट्रैक्टर-ट्रॉली की प्रारंभिक तलाशी ली, लेकिन उसमें कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली। इसके बाद टीम ने वाहन की बारीकी से जांच शुरू की और चालक से पूछताछ की। जांच के दौरान अधिकारियों को ट्रॉली के ढांचे और हाइड्रोलिक सिस्टम के बीच एक गुप्त चैंबर नजर आया। अधिकारियों के अनुसार, चैंबर को इस तरह बनाया गया था कि उसमें मादक पदार्थ छिपाया जा सके।

चैंबर खोलते ही मिले डोडाचूरा के पैकेट

गुप्त चैंबर खोलने पर उसमें डोडाचूरा के पैकेट मिले। टीम ने मादक पदार्थ को बाहर निकालकर उसका वजन कराया, जो कुल 123.630 किलोग्राम निकला। CBN ने बरामद डोडाचूरा और ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर लिया। चालक को एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है।

MP से कहां आया, किसे पहुंचाना था? जांच जारी

कार्रवाई के बाद CBN अब डोडाचूरा की पूरी सप्लाई चेन का पता लगाने में जुटी है। जांच की जा रही है कि मादक पदार्थ मध्यप्रदेश में कहां से लाया गया था और बिजौलिया क्षेत्र में इसे किस व्यक्ति तक पहुंचाया जाना था। एजेंसी तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। पूछताछ और जांच के आधार पर इस मामले में आगे और गिरफ्तारियां होने की संभावना है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक संपादकः नीरज मेहरा द्वारा बोनस ग्राफिक्स, लक्ष्मी नगर, झोटवाड़ा मार्ग, अजमेर रोड़, जयपुर-302006 से मुद्रित एवं 141, दयानन्द नगर, फेज प्रथम झालाना डूंगरी गली नंबर 19, थाना गांधी नगर, जयपुर (राज.) से प्रकाशित। प्रबंध संपादक- पी.के.बृजवाल, 9950325930, 9571635930 (कानूनी सलाहकार एडवोकेट कैलाशनाथ भट्ट)